**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**तारांकित प्रश्न सं. 314 का उत्तर**

**सामाजिक राज-सहायता को समाप्त किया जाना**

\***314. श्री कपिल सिब्बलः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तीस हजार करोड़ रुपये मूल्य की दी जा रही सामाजिक राजसहायता को समाप्त करने की योजना बना रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु रेलवे ने दो वित्तीय संस्थानों को नियुक्त किया है, यदि हां, तो इन संस्थानों का ब्यौरा क्या है तथा इस सर्वेक्षण पर कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) क्या इस संबंध में बैठकें आयोजित की गई हैं, यदि हां, तो अब तक हुई बैठकों तथा उन बैठकों का कार्यवृत्त संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

 **रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

सामाजिक राज-सहायता को समाप्‍त किए जाने के संबंध में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री कपिल सिब्‍बल के तारांकित प्रश्‍न सं.314 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): पैसेंजर और फ्रेट सेगमेंट में कोई सब्‍सिडी नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेल कतिपय परिवहन सेवाएं चलाती है, जो अलाभप्रद किस्‍म की होती हैं और इन्‍हें देश के बृहद हित में चलाया जाता है। भारतीय रेल में टैरिफ पॉलिसी यात्री किरायों में बढ़ोतरी के संबंध में पारंपरिक रूप से एक प्रतिबंध है। भारतीय रेल को अनेक अलाभप्रद सेवाएं चलाने पर प्रत्‍येक वर्ष हानि उठानी पड़ती है। ये हानियां अधिकांशत: (i) साधारण द्वितीय श्रेणी के कम किराए (ii) उपनगरीय और अनुपनगरीय सीज़न टिकटों के कम किराए (iii) अनिवार्य वस्‍तुओं की कम लागत की ढुलाई से हानि और (iv) यात्री टिकटों पर अनेक किस्‍म की रियायतों के कारण हैं। अलाभप्रद शाखा लाइनों का परिचालन भी भारतीय रेलों के वित्‍त पर भारी बोझ है। इस प्रकार इन सेवाओं के जरिए अर्जित राजस्‍व आय और इनकी लागतों के बीच अंतर रहता है।

(ख): भारतीय रेल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ पब्‍लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) को नियुक्‍त किया है, जो भारतीय रेलों द्वारा वहन किए जा रहे सामाजिक सेवा दायिता (एसएसओ) का मूल्‍यांकन करने हेतु विकसित तंत्र का अध्‍ययन करेगा, जिसके लिए 13.07.2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। एनआईपीएफपी को इस अध्‍ययन के लिए 29,50,000/- रुपए (जीएसटी सहित) का भुगतान किया गया है।

(ग): एनआईपीएफपी ने 28.11.2017 को भारतीय रेल की सामाजिक सेवा दायिता पर रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*\*